

प्रेषक,

सचिव,  
न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तरांचल शासन ।

जाग्र  
१५/२

सेवा में,

महाधिवक्ता,  
उत्तरांचल,  
नैनीताल ।

न्याय विभाग

देहरादून, दिनांक, ७ मई, २००३

विषय :-

मा० उच्च न्यायालय में रिट याचियों द्वारा अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन को लेकर प्रायः रिट कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया जाता है जबकि मुख्य सचिव विभाग विशेष के नैतिक कार्यों को नहीं देखते हैं बल्कि वे विभागीय सचिव द्वारा देखे जाते हैं । मुख्य सचिव को अवमानना याचिका में विपक्षी योजित वारने से प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल करने की कार्यवाही में उनका बहुमूल्य समय व्यर्थ जाता है साथ ही एक अवांछित परिपाठी भी बनती है । किसी प्रकरण में यदि अवगानना की स्थिति उत्पन्न मानी भी जाय तो इसके लिए विभागीय सचिव को विपक्षी बनाया जाना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निवेश हुआ है कि अपने स्तर से विधि अधिकारियों को निर्देश दें कि उन्हें जिस मामले में भी यह जानकारी उपलब्ध हो कि मुख्य सचिव को भी नित्यधर्या (routine) के रूप में अवमानना नोटिस जारी हुआ है वहाँ पर वे मा० उच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि मुख्य सचिव अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं हैं बल्कि विभागीय सचिव को ही नोटिस देना सचिव अवमानना के लिए उत्पन्न होने से शासन के अन्य कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है ।

कृपया उक्त स्थिति सभी राज्य विधि अधिकारियों के संज्ञान में लाकर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

SC (दी० लाल)  
सचिव

संख्या: २५६(२), न्याय विभाग/२००३, तिथिंक ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

SC (दी० लाल)  
सचिव